

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री बी.एल.कोठारी

आई.ए.एस.

प्रार्थी
युको बैंक शाखा सांचौर जरिये प्राधिकृत
अधिकारी

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री दिलीप कुमार खत्री पुत्र श्री भरत भाई
2. श्रीमती सीता देवी पत्नि श्री भरत भाई निवासी प्लोट
नंबर 511 हिंगलाज नगर मोजिया बास सांचौर

विविध प्रकरण संख्या

16/2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तित्वो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,
2002

.....

अधिवक्ता:-श्री नवीन गहलोत, अधिवक्ता प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक:- 25.06.2018

1- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तित्वो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।
2- प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण/ऋणी को रूपये 6,00,000/की ऋण सुविधा दिनांक 15.04.2015 को टर्म लोन के बाबत उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में श्रीमति सीतादेवी पत्नि श्री भरत भाई की मकान /प्लोट नंबर 511 हिंगलाज नगर मोजिया बास सांचौर में स्थित आवासीय जायदाद मय इमारत, बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट को बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उक्त सम्पति बंधक किये जाने योग्य है। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी की सम्पति को बंधक किया गया था। मूल टाईटल डीड बतौर रहन बैंक के पास रखे है। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 29.04.2017 को एन.पी.ए घोषित कर दिया गया व अप्रार्थीगण/ऋणी के ऋण खाते में राशि रूपये 5,69,339/- दिनांक 31.01.2017 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान ना करने पर एन.पी.ए घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13(2)के अन्तर्गत बैंक ने ऋणी अप्रार्थी को दिनांक 17.08.2017 को नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्त के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न ही हाईपोथीकेटेडशुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि कुल रूपये 5,69,339/- दिनांक 31.01.2017 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करना था। परन्तु ऋणी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं कराई, के कारण एक्ट की धारा 13(4) in case the Borrower fails to discharge his liability in full with in the period of specified in sub-section (2) the secured creditor may take recourse to take possession of the secured assets of the borrower including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realising the secured asset के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा 14(1) where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured creditor or if any of secured asset is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this act the secured creditor may for the purpose of taking possession or control any such secured asset request in writing the chief metropolitan magistrate or the district magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof or the chief metropolitan magistrate or as the case may be the district magistrate shall on request being made to him (a) take possession of such asset and documents relating there to 14(3) no act of the chief metropolitan magistrate or the district magistrate done in pursuit of this section shall be called in this question or in any court or before any authority के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियो से कब्जा लेने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेंट्स का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। बैंक सिक्योरिटीज का विवरण:- श्रीमति सीतादेवी पत्नि श्री भरत भाई की मकान /प्लोट नंबर 511 हिंगलाज नगर, मोजिया बास सांचौर जिला जालोर में स्थित आवासीय जायदाद मय इमारत बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट। उत्तर में प्लोट नंबर 512, दक्षिण में 10 फीट रोड, पूर्व में अन्य भूमि, पश्चिम में 30 फीट रोड। उक्त बंधक जायदाद सांचौर जिला जालोर में स्थित है जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

अतः प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वर्णित सम्पति का कब्जा व संबंधित डोक्यूमेंट्स का कब्जा ऋणी से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने के आदेश फरमावे।

3- पत्रावली का अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से 6,00,000/-रूपये (रु.छ: लाख) का ऋण/सुविधा स्वीकृत किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये ऑर्डिनेन्स की धारा 13(2) के तहत 17.08.2017 को समस्त प्रतिवादी को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनों में 5,69,339/- (अक्षर: पांच लाख उनसितार हजार तीन सौ उनचालीस रूपये मात्र) जिसमें दिनांक 31.01.2017 तक का ब्याज सम्मिलित है। प्रतिवादियो ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के बावजूद बैंक की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है।

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- (1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्हीं प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा। (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक, जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपत्तियों, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना सांचोर को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर